

प्रपत्र,

अनूप दधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संज्ञा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक-२२ दिसम्बर, 2008

विषय: नगर पालिका परिषद, विकासनगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-2008-09 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 688/V-श०वि०-०६-६७(सा०)/०६, दिनांक 25-3-2006 तथा शासनादेश संख्या 231/IV(2)-श०वि०-०८-६७(सा०)/०६ दिनांक 29-3-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, विकासनगर जनपद देहरादून हेतु रू०-454.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः रू० 142.60 लाख तथा रू० 80.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गई तथा न्यूनतम निविदा के आधार पर क्रमांक-1 तथा क्रमांक-3 के कार्यों में हुई बचत धनराशि रू० 1.25 लाख का समायोजन करते हुए इन कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः रू० 144.30 लाख तथा रू० 86.10 लाख प्रदान की गयी थी। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर के पत्र दिनांक 17-11-2008 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 25-3-2006 के द्वारा स्वीकृत क्रमांक-1 तथा क्रमांक-3 के लिए अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग के उपरान्त इन कार्यों हेतु अब स्वीकृति हेतु अवशेष रू० 77.73 लाख के सापेक्ष रू. 77.73 लाख (रूपये सत्तहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि रू. 77.73 लाख (रूपये सत्तहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तों का अनुपालन होने तथा कार्य का भौतिक सत्यापन होने पर ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 688/V-श०वि०-०६-६७(सा०)/०६, दिनांक 25-3-2006 तथा शासनादेश संख्या 231/IV(2)-श०वि०-०८-६७(सा०)/०६ दिनांक 29-3-2008 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रतः धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

5. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तत्काल उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप उत्तरदायी होंगे।
7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पाए गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोद्देश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि तथा को दिनांक 31-3-2009 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- वक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत मदों का लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अनुदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-957/XXVII(2)/2008, दिनांक- 10 दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

सं-11/11/1 (1)/IV(2)-शा0वि0-08, तददिनांक 22/12/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आशुप्रत, मन्डवाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. वरिष्ठ कांषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यापक/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. मर्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार ठाकुर)
अपर सचिव।